स्टार्टअप पॉलिसी में होंगे जरूरी संशोधन : सागर

प्रमुख सचिव आईटी ने किया एकेटीयू में यूपी इनक्यूबेटर्स मीट का शुभारंभ

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने कहा कि यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को बने करीब चार साल बीत गए है। अब समय आ गया है कि इसका परीक्षण कर जरूरी संशोधन किया जाएं। जिससे इनक्यूबेशन सेंटर व इनक्यूबेटीज को अधिक सरलता से आगे बढ़ाया जा सके। वह शुक्रवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में दो दिवसीय यूपी इनक्यूबेटर्स मीट का उद्घाटन कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में अमेरिका स्टार्टअप की महाशक्ति बन गया हैं। वहां जितने भी सफल आविष्कार हुए वो सब स्टार्टअप से निकले। स्टार्टअप किसी देश को आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इनक्यूबेशन सेंटर्स की समस्याओं का समाधान कर उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है।

एकेटीयू में शुक्रवार को यूपी इनक्यूबेटर्स मीट का शुभारंभ किया गया। स्रोत : विवि

कहा- स्टार्टअप किसी देश को आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण

कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने कहा कि किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप का बड़ा योगदान होता है। अमेरिका की कुछ कंपनियां वहां की जीडीपी में पचास फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती हैं। हमारा देश सर्विस देने और तकनीकी को प्रयोग करने में अग्रणी है। मगर प्रोडक्ट बनाने और पेटेंट में बहुत पीछे हैं। जब तक हम पेटेंट नहीं कराएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए इन्क्युबेशन सेंटर्स को अपने स्टार्टअप को पेटेंट करने के साथ ही उनके व्यवसायीकरण पर ध्यान देना होगा।

कार्यक्रम में 63 इनक्यूबेशन सेंटर के इनक्यूबेटर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रबंध निदेशक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि. रवि रंजन, इनोवेशन हब के महीप सिंह, कार्यक्रम में डीन इनोवेशन प्रो. बीएन मिश्रा, एसोसिएट डीन डॉ. अनुज कुमार शर्मा आदि मौजूद थे।